

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

30.06.2016 की स्थिति के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (3) के अधीन मानीटरिंग और रिपोर्ट

November, 2016 माह के दौरान प्राप्त कुल आवेदन : 92 और प्राप्त राशि: रु. 80/-

[illegible]

[illegible]

भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्विष्ट करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को दर्शाते हैं																
(छ) सुधार के लिए समुचित सुझाव जो विज्ञप्ति, सुधार, आधुनिकीकरण एवं सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के लिए इस अधिनियम अथवा अन्यम विधान अथवा सामान्य विधि अथवा अन्यम किसी संगत मामले में संशोधन के लिए सुधार के लिए अपेक्षित हो																

**** विभाग की वेबसाइट <http://darp-grievance.nic.in> में भारत में कहीं भी, किसी भी वेब आधारित सुविधा के जरिए कोई भी नागरिक शिकायतें दर्ज करा सकता है ।**